

जात आधारित जनगणना

प्रलिस के लयः

जनगणना, एसईसीसी, ओबीसी ।

मेन्स के लयः

जात आधारित जनगणना और संबधति मुद्दे, जनसंख्या और संबध मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी जातियों और समुदायों (SECC) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करेगी ।

जनगणना और SECC के बीच अंतरः

■ जनगणनाः

- भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई ।
- जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आँकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुँचने, सामाजिक परिवर्तन, **प्रसिमान** से संबंधित आँकड़े आदिका उपयोग करने के लिये किया जाता है ।
- हालाँकि 1940 के दशक की शुरुआत में वर्ष 1941 की जनगणना के लिये भारत के जनगणना आयुक्त 'डब्ल्यू. डब्ल्यू. एम. यीट्स' ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी, बेहद मज़बूत अवधारणा है लेकिन **वशिष जाँच** के लिये यह एक **अनुपयुक्त साधन** है ।

■ सामाजिक-आर्थिक और जातगत जनगणना (SECC):

- वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था ।
- SECC का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की नमिनलखित स्थितियों के बारे में पता करना है:
 - **आर्थिक स्थिति** पता करना ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी और संचयी संकेतकों की एक शृंखला प्राप्त करने तथा उन्हें इसमें शामिल करने की अनुमति दी जा सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सकता है ।
 - इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसका **वशिषित जातगत** नाम पूछना है, जिससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी हो कि कौन से जातिसमूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में थे और कौन बेहतर थे ।
- SECC में व्यापक स्तर पर '**असमानताओं के मानचित्रण**' की जानकारी देने की क्षमता है ।

■ जनगणना और SECC के बीच अंतरः

- जनगणना भारतीय आबादी का एक **समग्र चित्र प्रस्तुत** करती है, जबकि SECC राज्य द्वारा सहायता के योग्यलाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय/साधन है ।
- चूँकि जनगणना, वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, इसलिये **सभी आँकड़ों को गोपनीय** माना जाता है, जबकि SECC की वेबसाइट के अनुसार, "SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का **उपयोग कर सरकारी विभाग** परिवारों को लाभ पहुँचाने और/या प्रतबंधित करने के लिये स्वतंत्र है ।

जात आधारित जनगणना आयोजित करने के पक्ष और वपिक्ष में तर्कः

■ पक्ष में तर्कः

○ सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहायकः

- भारत के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते हैं और जातजनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी ।
- डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूह के लिये कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है ।
- **मंडल आयोज** ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 5% है, जबकि कुछ अन्य ने ओबीसी आबादी के 36 से 65% तक होने का अनुमान लगाया ।

- जात/आधारित जनगणना के माध्यम से 'OBC आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा OBC की आर्थिक स्थिति (घर के प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय) के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकीय जानकारी (लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा), शैक्षणिक डेटा (पुरुष और महिला साक्षरता, स्कूल जाने वाली आबादी का अनुपात, संख्या) प्राप्त होगा।

○ आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता उपाय:

- जात-आधारित जनगणना आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता का उपाय लाने में लंबा रास्ता तय कर सकती है।
- OBC के लिये 27% कोटा के समान पुनर्वितरण की जाँच के लिये गठित **रोहिंगी आयोग** के अनुसार, ओबीसी आरक्षण के तहत लगभग 2,633 जातियाँ शामिल हैं।
- हालाँकि 1992 से केंद्र की आरक्षण नीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि OBC के भीतर अत्यंत पछिड़ी जातियों की एक अलग श्रेणी मौजूद है, जो अभी भी हाशिये पर हैं।

■ वपिक्ष में तर्क:

- **जात/आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव:** जात में एक भावनात्मक तत्त्व नहिता होता है और इस प्रकार जात/आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
 - ऐसी आशंकाएँ प्रकट होती रही हैं कि जात संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मलि सकती है।
 - इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातगत जनगणना, 2011 के लगभग एक दशक बाद भी इसके आँकड़े के बड़े अंश अप्रकाशित रहे हैं या ये केवल अंशों में ही जारी किये गए हैं।
- **जातसंदर्भ-वशिष्ट होती है:** जात/किभी भी भारत में वर्ग या वंशना का छद्म रूप नहीं रही; यह एक वशिष्ट प्रकार के अंतरनिहित भेदभाव का गठन करती है जो प्रायः वर्ग के भी पार चला जाता है। उदाहरण के लिये:
 - दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जात के उम्मीदवार से बेहतर हो।
 - जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किये जाने की संभावना भी कम होती है।
 - एक पढ़े-लिखे, संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जात/कि महिलाओं के परिवारों में हसिक प्रतशिोध को जन्म देता है।

आगे की राह

- एक जात/जनगणना जातविहीन समाज के लक्ष्य के लिये भले ही अनुकूल न हो लेकिन यह समाज में **असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है।**
- जात/के आँकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता कसि है और कसि नहीं, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि लाएगा।
 - नषिपक्ष डेटा और उसके बाद के शोध सबसे पछिड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जात/व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं तथा यह उन दोनों पक्षों के लोगों के लिये सही सूचना के स्रोत हो सकते हैं जो आरक्षण के पक्ष या उसके वपिक्ष में हैं।
 - आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि **आरक्षण का दुपयोग हमारे समाज में वभिजन पैदा** करता है।

वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर (घातीय) तीन गुना हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- जनसंख्या की सघनता के महत्त्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व है। इसे प्रतिवर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में प्रभाषित किया जाता है।
- वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था और 1951 में यह 117 था। इस प्रकार घनत्व में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई, न कि तीन गुना। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- बीसवीं सदी की शुरुआत यानी वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 था और यह लगातार एक दशक से बढ़कर वर्ष 2001 में 324 तक पहुँच गया।
- वर्ष 2001 में औसत वार्षिक वृद्धिदर 1.93 थी, जबकि 1951 में यह 1.25 थी। इस प्रकार इसमें वृद्धि तो हुई लेकिन यह वृद्धिदोगुनी नहीं थी। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

अतः वकिल्प (D) सही है।

स्रोत: द हट्टु

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/caste-based-census>

